Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

चुनावी रेवड़ी की राजनीति : एक अध्ययन

मनोज अहिरवार*

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय ,उज्जैन (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी –चुनाव, रेवड़ी, फ्रीबीज, राजनीतिक दल, योजनाएं, जनकल्याण, मतदाता आदि।

प्रस्तावना – चुनावी रेवड़ी या फ्रीबीज यह शब्द वर्तमान राजनीति में प्रमुख रूप से देखने को मिल रहे हैं। रेवड़ी एक प्रकार की भारतीय मिठाई है।रेवड़ी मुख्यतौर पर तिल को चीनी या गुड़ में मिलाकर बनाया जाता है। रेवड़ी का नाम आते ही मुंह में एक मिठास और मन में लोहड़ी जैसी मस्ती घुल जाती है। तिल की वजह से रेवड़ी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। हालांकि राजनीतिक रेवड़ी का स्वाद इसके ठीक विपरीत होता है। चुनावी वादों के तौर पर वोटरों के बीच बंटने वाली ज्यादातर रेवड़ी, उन्हें कभी नहीं मिलती। सत्ता में आने के बाद वोटरों को लुभाने के लिए जो रेवड़ी बांटी जाती है, उससे सरकारी खजाना खाली होता है। दीर्घकाल में इसका सीधा दुष्प्रभाव बड़ी परियोजनाओं और राज्य के विकास पर पड़ता है।भारत में चुनाव एक तरफ जहां मूलभूत सुविधाओं तथा जनकल्याण के मुद्दों पर लड़े जाते थे, वहीं कुछ समय से एक नया तरीका सामने आया है, जिसे चुनावी रेवड़ी अथवा फ्रीबीज कहते हैं। फ्रीबीज शब्द सबसे पहले 1920 के दशक में अमेरिकी राजनीति में इस्तेमाल हुआ था। फ्रीबी शब्द का मतलब होता है, कोई ऐसी चीज जो आपको मुफ्त में दी जाती है। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, फ्रीबीज की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। प्राकृतिक आपदा या महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवाएं, खाना या पैसा मुहैया कराने से लोगों की जान बच सकती है, लेकिन आम दिनों में अगर ये दिए जाएं तो इन्हें फ्रीबीज कहा जाएगा। इसमें विभिन्न राजनीतिक दल वोट अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिए तरह–तरह की फ्री योजनाएं और लोक लुभावन वादे करते हैं । चुनाव के कुछ दिन पहले ही ऐसी योजनाओं को जनता के बीच में लाया जाता है, और उन्हें अपने पक्ष में वोट करने के लिए आकर्षित किया जाता है। वैसे तो इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन चुनाव के कुछ समय पहले राजनीतिक दलों द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, उनमें से कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं होती हैं । जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता, फ्री मोबाइल, टीवी ,वाशिंग मशीन इत्यादि। जो जनता को दी जाती हैं। इसके अलावा नगद राशि जो किसी योजना के रूप में जनता को दी जाती है। यह सभी रेवड़ी की श्रेणी में आती हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा या अन्य कोई चुनाव सभी में अब इसका प्रभाव देखने को मिलने लगा है।

'गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया।'

इन योजनाओं को सभी अपने–अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। जो राजनीतिक दल इसकी घोषणा करता है, वह इसे लोक कल्याणकारी योजना कहता है। तथा विपक्ष इसे रेवड़ी या मुफ्तखोरी कहता है। लेकिन इस तरह की योजनाएं लगभग सभी प्रमुख दलों द्वारा चलाई जा चुकी हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में रहते हैं, वह चुनाव के पूर्व राजकोष से इन योजनाओं की घोषणा करते हैं, तथा अन्य दल सरकार बनने के बाद इस तरह की योजनाओं को शुरू करने की गारंटी देते हैं। लेकिन दोनों ही सरकारी धन के बल पर यह करते हैं।

जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी तथा महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस तरह की चुनावी रेवड़ी का विरोध किया गया था। वर्ष 2022 में भाजपा ने ही इस प्रकार की योजनाओं को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। लेकिन उनकी ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लाडली बहन योजना प्रारंभ की। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने भी माझी लाडकी बहन योजना शुरू की। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा प्रारंभ की। तेलंगाना में रायतू बंधु योजना। इस प्रकार लगभग अधिकांश राज्यों के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की योजनाएं जिनका जनता को प्रत्यक्ष लाभ जो फ्री में उपलब्ध कराया जाता है चुनावी रेवाड़ी या फ्रीबीज है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास – चुनावी रेवड़ी की संकल्पना नई नहीं है, यह तो दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए मुफ्त की योजनाओं या फ्रीबीज का ऐलान करती रहीं हैं।भारत में इसकी शुरुआत दक्षिण के राज्यों से हुई और धीरे–धीरे यह पूरे भारत में फैल गई ।इस प्रकार की योजनाएं कैसे और कहां शुरू हुई इसके विकास को देखते हैं जैसे

मद्रास स्टेट के सीएम के कामराज ने 1954 से 1963 के दौरान मुफ्त शिक्षा और स्कूली छात्रों के लिए मुक्त भजन जैसी स्कीम शुरू की।

1967 में DMK के संस्थापक कम अन्नादुरई ने तमिलनाडु चुनाव में एक रुपए में 4.5 किलो चावल देने जैसे वादे किए थे।

1982 में एमजी रामचंद्र ने कामराज की तरह ही तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन की योजना लागू की थी।

1980 के दशक में आंध्र प्रदेश के एम एंटी रामाराव ने रू 2 किलो चावल देने की योजना शुरू की थी।

1990 के दशक में तमिलनाडु ।प्।क्ड्ड नेता जे जयललिता ने मुफ्त

साड़ी, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और वाशिंग मशीन देने जैसे वादे किए थे। 1990 के दशक में ही पंजाब में अकाली दल सरकार ने सबसे पहले मुफ्त बिजली देना शुरू किया था।

2006 विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके ने वोटर्स को कलर टीवी देने का वादा किया था।

तमिलनाडु के चुनाव में गैस स्टोव, कैश, जमीन और मैटरनिटी सहायता तक देने का वादा करती रही है।

2015 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोगों को मुफ्त बिजली और पानी देने के साथ ही सत्ता में आई।

2022 में पंजाब में सत्ता में आई आप सरकार ने जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना शुरू कर दी थी।

2022 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी योजना शुरू की थी।

गुजरात में बीजेपी सरकार ने 4000 गांव के लिए मुक्त वाई-फाई और गाय संरक्षण के लिए 500 करोड़ देने का वादा किया था।

आमआदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जीतने पर 300 यूनिट बिजली फ्री और हर माह महिलाओं को रू 1000 देने का वादा किया था।

मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव के पहले लाडली बहन योजना के माध्यम से रू1000 महीना महिलाओं को देना शुरू किया। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन सरकार ने महिलाओं माझी लड़की बहन योजना के माध्यम से उनको रू 1500 महीना देना प्रारंभ किया।इस तरह लगभग सभी राज्यों में सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाएं देते आ रहे हैं।

उद्देश्य:

1. चुनावी रेवड़ी या फ्रीबीज क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसका विश्लेषण करना।
2. रेवड़ीयाफ्रीबीज कल्चर के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. फ्रीबीज को कैसे बंद किया जा सकता है, इसका अध्ययन करना।

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध आलेख में विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कर अध्ययन किया गया है। तथ्यों के संकलन में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से तथ्य संग्रहित किए गए हैं। जिसमें विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाएं, शोधपत्र, चुनावी घोषणा पत्र, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि को शामिल किया गया है।

प्रभाव:

राजनीतिक प्रभाव– चुनावी रेवड़ी का प्रभाव सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों पर देखने को मिल रहा है। कुछ दल इसका प्रयोग चुनाव में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और उसका फायदा उनको चुनावी नतीजे में स्पष्ट तरीके से देखने को मिल रहा है। जिन चुनावों में उनका मत प्रतिशत बहुत कम रहता था, रेवड़ी/फ्रीबीज के माध्यम से मत प्रतिशत भी बड़ा और उनकी जीत भी हुई, एवं सरकार भी बनी। इसको देखते हुए अन्य दल भी ना चाहते हुए भी फ्री में योजनाओं की घोषणा कर देते हैं, ताकि उनको भी जीत मिल सके।

सामाजिक प्रभाव– इससे मतदाताओं में लालच उत्पन्न हो जाता है, और वह इससे भी ज्यादा फ्री की योजनाओं की आशा रखने लगते हैं। मुफ्तखोरी से पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। इससे प्रदूषण भी बढ़ सकता है मुफ्त की चीजें सरकार पर निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती हैं।

आर्थिक प्रभाव– आरबीआई ने हाल ही में एक अध्ययन किया है। राज्य वित्त एक जोखिम विश्लेषण ।इस अध्ययन के अनुसार भारतीय राज्यों के लिए हाल के वर्षों में सब्सिडी पर सरकारी ब्याज 11 से 12% की दर से बड़ा है। आरबीआई के अनुसार कई राज्य सरकारें सब्सिडी से मुफ्त की योजनाओं पर स्विच कर रही हैं। 2023-24 में सरकार को राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% रहने का अनुमान था। इसके 5.02 प्रतिशत से 5.4% तक जाने की उम्मीद है। राज्यों को 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति है, जिसमें 0.5% बिजली सुधार के लिए है।

मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से सार्वजनिक वित्त पर बोझ काफी बढ़ता है। जिसकी लागत कई राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 0.1% से 2.7% तक होती है। कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश और पंजाब अपने राजस्व का 10% से अधिक सब्सिडी के लिए आवंटन करते हैं। ऐसे में राजकोषीय हालात पर असर पड़ता है।

रेवड़ी/ फ्रीबीज का वैश्विक परिदृश्य – चुनावी रेवड़ी को वैश्विक संदर्भ में देखें तो ज्ञात होता है, कि यह एक वैश्विक समस्या है। कई देशों में राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त सुविधाएं और उपहार देते हैं। यह समस्या केवल भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी है। जहां रेवड़ी फ्रीबीज के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। इनमें श्रीलंका, अर्जेंटीना, अमेरिका जैसे देश शामिल है।

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई। और उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। क्योंकि वहां की सरकार ने फ्रीबीज को बहुत बढ़ावा दिया जिसमें जनता की बहुत सारे कर माफ कर दिए और सब्सिडी बहुत अधिक दी जिससे देश पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। ऐसा ही अर्जेंटीना में भी रेवड़ी कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। विश्व के बहुत से देशों में फ्रीबीज कल्चर का प्रचलन देखने को मिल रहा है। इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर भी प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

सुझाव –चुनाव में इस तरह के रेवड़ीकल्चर को रोकने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे-धीरे पूरी चुनावी प्रक्रिया केवल इन्ही योजनाओं पर संचालित होने लगेगी। और आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेवड़ी या फ्रीबीज को परिभाषित किया जाए तथा साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं और फ्रीबीज के मध्य अंतर को स्पष्ट किया जाए। जनता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जाएं, और उन्हें समझाया जाए कि ऐसी योजनाओं के नाम पर मतदान न करें। मतदान करते वक्त एक सशक्त और जनकल्याण वाली सरकार का चुनाव करें। रेवड़ी कल्चर को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा कानून बनाया जाए। जिसकी वजह से कोई भी राजनीतिक दल इस रेवड़ी कल्चर को ना अपना सके।

निष्कर्ष – पिछले दशक से भारत के लगभग आधे से अधिक राज्यों में रेवड़ी कल्चर एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इसको ही प्राथमिकता देने लगे हैं। मतदाता भी प्रत्यक्ष लाभ के कारण उन्हीं के पक्ष में मतदान करते हैं। तथा उनको ही सत्ता में ला रहे हैं। वर्तमान राजनीति में देखा जाए तो प्रत्येक राजनितिक दल ने चुनावो में जीतने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया है। और वह है फ्री की योजनाएं जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, और भी कई योजनाएं हैं जिनको चुनावी रेवड़ी या मुफ्तखोरी कहा जा सकता है। जो राजनीतिक दल सत्ता में है वह मनमाने ढंग से इस तरह की योजनाएं

चालू कर देते हैं ताकि उनको आगामी चुनाव में जीत हासिल हो सके। इसी को देखते हुए अन्य दल भी सत्ता में आने के लिए मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने लगते हैं। इस प्रकार सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही रेवड़ी कल्चर को बड़ावा देते हैं। और साथ ही एक दूसरे की योजनाओं को फ्रीबीज या रेवड़ी बोलते हैं और अपनी योजनाओं को कल्याणकारी बताते हैं। रेवड़ी कल्चर को रोकना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और लगातार कई राज्य कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद इन सभी को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए, कि इस कल्चर को जल्दी ही बंद कराया जा सके। सभी राजनीतिक दलों को भी चुनावी रेवड़ी जैसी योजनाओं को बंद करना चाहिए। तथा मूलभूत और आवश्यक सुविधाओं के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। मतदाताओं को भी यह सोचना होगा कि यह जो फ्री की योजनाएं हैं, वह उनके विकास में बाधक हैं, उनके आधार पर मतदान नहीं करना चाहिए। जब यह योजनाएं फेल होने लगेंगी और इनके माध्यम से चुनाव में जीत नहीं मिलेगी तो धीरे–धीरे ये स्वत: ही समाप्त होने लगेंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आजतक 17/08/2022,https://youtu.be/7-TL3sTQZnU?si=gAJUvd9jjUgCqbNh
2. दीपिका पल 9(11/2024, https://navbharatlive.com/special-coverage/formula-of-throwing-sweets-and-winning-the-election-is-in-vogue-in-electoral-democracy-1053412.html
3. सुनीलकुमार 03/12/2024, https://www.jagran.com/business/biz-freebies-will-reduce-gdp-growth-in-fy-202425-23841416.html
4. NDTV Profit desk 14/10/2023, https://hindi.ndtvprofit.com/politics/india/who-is-benefiting-from-freebies-in-election-assembly-election-in-five-states
5. विजय कुमार 4/12/2024, https://hindi.oneindia.com/news/features/what-is-freebies-what-is-the-difference-from-subsidy-735085.html
6. दिनेश मिश्र 10/12/2024, https://navbharattimes.indiatimes.com/india/will-free-electricity-water-and-ration-stop-why-did-supreme-court-get-upset-over-distributing-freebies/articleshow/116168531.cms
7. शादाब नज्मी 01/04/2024, https://www.bbc.com/hindi/articles/crgdlep95l5o
8. योगेश यादव 08/12/2024, https://4pm.co.in/the-economy-of-the-states-has-collapsed-due-to-distribution-of-free-revadi-the-country-is-drowning-in-debt/114221
9. आलोक जोशी 10/11/2024, https://www.livehindustan.com/ blog/editorial-news/hindustan-editorial-column-11-november-2024-story-201731262486299.html
10. अभिषेक पांडे 23/08/2022, https://www.bhaskar.com/db-original/explainer/news/freebies-controversy-history-explained-arvind-kejriwal-modi-government-supreme-court-130218673.html

****